

शुआट्स फोटोग्राफी कल्ब द्वारा विदाइ समारोह का आयोजन

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

प्रयागराज। शुआट्स फोटोग्राफी कल्ब द्वारा एसपीसी के अधिकारियों और सदस्यों को सम्मानित किया गया और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता का जमाना की गई डॉ. वेस्टी ने आने वाले सदस्यों वाले



डॉ. सी.ओ.जे. वेस्टी, एसपीसी सदस्यों को सम्मानित करते हुए

रीता जोशी, केशरी और अभिलाषा को नई भूमिका का इंतजार, लोकसभा चुनाव में नहीं मिला टिकट

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

प्रयागराज। भाजपा की इन तीरों ही अभिलाषा नेताओं की आगे पार्टी में क्या भूमिका होगी, उसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इन तीरों नेताओं को भी अपनी नई भूमिका का इंतजार है। हालांकि खुद की पार्टी का समर्पित सिपाही बताते हुए इन तीरों का यही भी दायित सौंपेंगी, उसका वह बखूबी निर्वाहन करेंगी। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही रीता बहुगुणा

शुभकामनाएं देते हुए 2024-25 सत्र के लिए नवगठित समिति को भी मजरी दी एसपीसी के सोशल मीडिया विश्लेषक और समन्वयक गौरव सुमन ने छात्रों को अपने फोटोग्राफी कौशल को लगातार बढ़ाने और सामाजिक सूधार के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह आयोजन कुत्तजाता और प्रेरणा का मिश्रण था, जिसने एसपीसी के बाहर जाने वाले और आगे वाले दोनों सदस्यों के लिए सकारात्मक माहील स्थापित किया।



भाजपा ने सांसद रीता बहुगुणा जोशी, सांसद केशरी देवी पटेल का दर्शन-पूजन करने के लिए आए थे। यहां गंगा सनन के लिए पहुंचे थे। तभी दो दोस्त अचानक दूर्बल लगे,

नहाने के दौरान दूबा कमाऊ महाकुंभ सामने, विकास कार्यों का गई दीर्घकालीन मिले लाभ, इस पर रहेगी नजर

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

प्रयागराज। गंगा में दूबा युवक अपने घर का कमाऊ बेटा था। पिता नहीं देख सकते मां बूढ़ी हो गई है। घर का पूरा जिम्मा युवक के कथे पर था। उसकी मौत की खबर पर परिजनों में कोहराम मच गया। वर्षी, विद्युत संविदाकर्मी की मौत से कुछ

उसके पिता दिनकर तुकाराम आये

जिसमें एक गहरे पानी के तरफ चला गया। युवकों ने अपना नाम ऋषिकेश, धनंजय, हरिश्याम, दीपक है। धनंजय ने बताया कि सागर महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूयूटी कर्मचारी था। उसके परिवार में माता-पिता और बहन हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस पर ही थी।

उसके पिता दिनकर तुकाराम आये

जिसमें एक गहरे पानी के तरफ चला गया। पिताजी (रेवती रमण सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी दो बार सांसद

रहे। अब लोगों का वही सेवा मुझे

नैनी में उदयोग को फिर से

स्थापित करने, केवर पावर प्लाट

पर प्रयास करूंगा। उदयोग के साथ ही रोजगार बढ़ेगा। पीडीए

की ओर से महायोजना-2031 अब

समर्थन दिया। गठबंधन के

कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव मानक

साथ दिया। पिताजी (रेवती रमण

सिंह) ने 50 वर्षों तक क्षेत्र के लोगों

की सेवा की। पिताजी द

सम्पादकीय

स्कूल में हल्के शारीरिक
दंड से बच्चा सुधरता है
तो हर्ज क्या है

भी आते हैं कि अभिभावकों ने उनका बच्चा बहुत लालंकिया बताया कि जब वो पांचवर्षीय कक्षा में थे तो एक गलती के लिए उन्हें उनकी टीचर ने बैंट से पीटा था। सप्तीम कोर्ट के मध्ये

सरकार ने किशो अधिनियम 2015 यानी जस्टिस एक्ट लागू किए बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए ग्राइडलाइंस बनाया। स्कूल में पिटाई को लेकर है। शिक्षा के अधिकार 2009 की धारा 17 में है कि स्कूल में किसी भी शारीरिक दंड, मानसिक और भेदभाव पूरी तरह है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में कहा गया बच्चे की देखभाल और सुरक्षा स्कूल की जिम्मेदारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 82 के अनुसार इन जेल और जुर्माने का प्रयोग ऐसे भी कई मामले आ गए। बच्चों के माता-पिता की जिम्मेदारी को स्कूल प्रबंधन नहीं ऐसे में माता-पिता को होता है कि वो नेशनल फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर राइट्स (एनसीपीसीआर) के जाकर शिकायत दर्ज करता है। एनसीपीसीआर के स्कूल में जिन लोगों ने पर रखा जाता है, उनका वेरिफिकेशन अनिवार्य है।

एक पक्ष ऐसा भी है, जो कहता है कि शिक्षक की पिटाई से बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक असर आता है और उसके दूरगामी पर दुष्परिणाम होते हैं। दूरअसल, ऐसी अनेक खबरें संचार माध्यमों में देखने को मिल जाती है कि शिक्षक की पिटाई से बच्चे का हथ टूट गया, कान का पर्दा फट गया या बच्चे की मौत तक हो गई। बात यह है कि आखिर बच्चों की पिटाई की सीमा क्या होनी चाहिए? क्योंकि पिछले साल ऐसे ही एक केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि टीचर द्वारा स्कूल में बच्चों को सही करना अपराध नहीं हो सकता, अगर उसका इरादा दूर्भावनापूर्ण नहीं हो। सीजेआई डीवाई चंद्रघूड़ के किस्से से एक बार फिर शिक्षकों द्वारा बच्चों की पिटाई का विषय चर्चा में आ गया है। सवाल यह है कि बच्चों को सुधारने के लिए यदि हल्का शारीरिक दंड दिया जाए तो क्या वो भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि कई उदाहरण ऐसे से एफडीवेट लेना जस वो पहले जुवेनाइल जरि और पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं होने चाहिए। सीबी गाइडलाइंस के तहत 35 किसी भी नियम का उल्लंघन है तो उसकी मान्यता रद्द सकती है। शारीरिक दंड शिक्षा को 10,000 जुर्माना हो सकता है। यह दाहराने पर तीन माह के प्रावधान है। शिक्षक दंड किया जा सकता है। सहयोग नहीं करने पर को 3 महीने की जगह प्रावधान है। स्कूल पर का जुर्माना लगाया जाता है। सवाल यह है कि यदि छोटा-मोटा शारीरिक सुधार जा सकता है तो वह क्या है। काठमांडू के कानून सीजेआई डी.वाई चंद्रघूड़ भी कि बच्चों के साथ बर्ताव का असर जिंदगी दिमाग पर रहता है। बिल्कुल सही है।

धर्मधिक रहे हैं धरती के फेफड़,
हो रहा पर्यावरण का विनाश।
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के
आंकड़ों के अनुसार देश का 36
प्रतिशत वनक्षेत्र अक्सर वनागिन्-से
थथकता रहता है और इसमें से
प्रति 4 प्रतिशत क्षेत्र वनागिन्-की दृष्टि
से अत्यंत संवेदनशील है। जबकि
प्रतिशत वनावरण अत्यधिक अगिन्-
वरण पाया गया है। धरती पर
जीवन जीने के लिए अति आवश्यक

विभाग के डैशबोर्ड पर 24 अप्रैल
की प्रातः उत्तर से लेकर दक्षिण
तक देश के 13 राज्यों में 62 वन
क्षेत्रों में भीषण आग लगी हुई थी,
जिनमें हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड
में सर्वाधिक 30 स्थानों पर जंगल
भर्यकर रूप से धू-धू कर जल रहे
थे। हिमालय पर लपटें कितनी
खतरनाक हैं, उसे बढ़ती दैवी

दहकते जंगल उगल रहे हैं बैक कार्बन, संकट में पर्यावरण

सबसे बड़ी चिन्ता का विषय तो यह है कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखण्ड इस दावानल से सर्वाधिक प्रभावित है जिसका सीधा असर उस हिमालय पर पड़ रहा है जिसे एशिया की जलवायु का नियंत्रक और महाद्वीप का जलसंभंया वाटर टावर कहा जाता है। इस समय आग जंगलों को निगल रही है और जंगल ढैंक कार्बन उगल रहे हैं। ग्रीष्म क्रतु के अपने चरम की ओर तेजी से बढ़ते जाने के साथ ही जंगलों में भड़की आग भी अपना विकराल रूप लेती जा रही है। हालात यह है कि जंगल की आग से उत्पन्न धूएं के घटाटोप में पहाड़ भी ढूबते नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को श्वांस जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सबसे बड़ी चिन्ता का विषय तो यह है कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखण्ड इस दावानल से सर्वाधिक प्रभावित है जिसका सीधा असर उस हिमालय पर पड़ रहा है जिसे एशिया की जलवायु का नियंत्रक और महाद्वीप का जलसंभंया वाटर टावर कहा जाता है। इस समय आग जंगल को निगल रही है और जंगल ढैंक कार्बन उगल रहे हैं। अगर आग भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग वनागिन्पोर्टल का अवलोकन करता तो उसमें पिछले 7 दिनों के दौरान उत्तराखण्ड का वनागिन्पे के सर्वाधिक लगभग 4500 अलर्ट उत्तराखण्ड को भेजे गए हैं। इस अवधि में सर्वाधिक 350 वनागिन्पी की बड़ी यात्रा गंभीर घटनाएं उत्तराखण्ड में दर्ज हुई हैं और उसके बाद बाद उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई है, उसमें 5 मई को प्रदर्शित देशभर में भड़की कुल बड़ी वनागिन्यों में रुक्के अकेले उत्तराखण्ड के जंगलों को 110 घटनाएं दर्शायी गई थी। इधर 8 मई 2024 को प्रातः 10 बजे तक देश में वनागिन्पी की 22 बड़ी घटनाएं दर्ज हुई जिनमें सर्वाधिक 15 भीषण वनागिन्यां उत्तराखण्ड की थीं जबकि डैशबोर्ड पड़ोसी हिमाचल में केवल 2 घटनाएं दिखा रहा था। इस वनागिन्पे आपदा में वन सम्पद के स्वाहा होने के साथ ही वन्यजीव

होने लगे हैं जिनमें सांस लेने में परेशानी भी शामिल है। इन अदृश्य संकटों में जलवायु परिवर्तन भी है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि जंगल की आग ब्लैक कार्बन के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब जंगल जलते हैं तो वे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन सहित अन्य प्रदूषक भी उत्सर्जित करते हैं। जंगल की आग से उत्पन्न ब्लैक कार्बन की मात्रा वनस्पति जलने के प्रकार, आग की तीव्रता और मौसम की स्थिति जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है और उन क्षेत्रों में जहां जंगल की आग अक्सर या तीव्र होती है वहां ब्लैक कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। चूंकि हरी वनस्पति ज्यादा कार्बन धारण करती है इसलिए जब वह जलती है तो उस कार्बन को गातावरण में उत्सर्जित कर देती है। इन उत्सर्जनों का वायु गुणवत्ता और जलवायु पर स्थानीय और वैश्विक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। यह अद्यतला कार्बन ही ब्लैक कार्बन

ोमास के अधूरे दहन से उत्पन्न हा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के निकों द्वारा वर्ष 2016 में गगोत्री योग्यर के पास चीड़वासा स्टेशन को क्रैके गए एक अध्ययन में इस में वानागिन्के कारण ब्लैक कार्बन (सी) की अधिकता की पुष्टि की है। ब्लैक कार्बन उत्सर्जन वृद्धि जल और पेट्रोल चालित वाहनों भी काफी योगदान माना गया विशेष रूप से पुराने डीजल न, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के चप्पूण स्रोत है। इसमें ट्रक, बस, और ट्रेन शामिल हैं। वाडिया एटोट्यूट के डॉ. पी. एस. नेगी के च में किए गए इस अनुसंधान वैज्ञानिक पत्रिका एटमॉस्फेरिक वायरनमेंट में प्रकाशित किया था। चूंकि अब गमियों में राखण्ड की चारधाम यात्रा के ही हिमालयी धर्मस्थलों पर भी बढ़ने वाली है। पिछले साल ले उत्तराखण्ड के चार धार्मों गंगभग 6 लाख वाहन पहुंचे थे। स बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के बर्फ और बर्फ के आवरण में गिरावट के लिए भारत से वायुजनित ब्लैक कार्बन एरोसोल एक प्रमुख योगदानकर्ता है। बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन और बायोमास को जलाने के परिणामस्वरूप उत्सर्जित होने वाले ब्लैक कार्बन का वास्तविक योगदान 30 प्रतिशत से भी अधिक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जंगलों की यह आग वातावरण में पर्याप्त मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों और सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन कर रही है। वानागिन्के कारण ब्लैक कार्बन जैसे तत्व झाड़ियों, घास के मैदानों और जंगलों से उत्सर्जित हो कर वातावरण में फैल जाते हैं। जैसे ही वनस्पति जलती है, उनके भीतर जमा कार्बन उत्सर्जित हो जाता है। यही मुख्य कारण है कि बड़े पैमाने पर जगल की आग गयुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ२) छोड़ती है और इसलिए, जलवायु परिवर्तन की दर को काफी हद तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ब्लैक कार्बन एक जलवायु को सीधी प्रभावित करता जिसका गुबल वर्मिंग में सीधा योगदान होता है। इसके अतिरिक्त, जब ब्लैक कार्बन बर्फ पर जम जाता है तो यह उनकी अल्बे डो (परावर्तनशीलता) को कम कर देता है, जिससे वे अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और तेजी से पिघल जाते हैं, जो समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु प्रभावों में योगदान कर सकता है। हिमालय पर इस भीषण वनागिन्कांड से बड़े पैमाने पर ब्लैक कार्बन और अन्य गैसों उत्सर्जित हो रही है जिससे एरासोल का सन्तुलन भी गड़बड़ा रहा है, जिसका सीधा असर लोकल और गुबल वर्मिंग के साथ ही हिमालयी ग्रुशियरों पर पड़ रहा है जो कि तेजी से पीछे खिसक रहे हैं। ग्रुशियरों पर ब्लैक कार्बन जमने की वजह से बर्फ की सौर किरणों को परावर्तित करने की क्षमता कम हो रही है और ग्रुशियरों की सतह पर जमे ब्लैक कार्बन सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिसकी वजह से ग्रुशियर तेजी से पिघलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी



जलवायु का नियंत्रक और महाद्वीप का जलसंसंभय या गाटर टावर कहा तो तबाह हो ही रहा है। लेकिन इससे वे अदृश्य संकट भी प्रकट

होता है। ब्लैक कार्बन मुख्य रूप से कार्बन-आधारित ईंधन और

निक सुरबी मेनन और उनके प्रयोगियों ने पाया कि ग्लैशियरों पर है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर वातावरण को गर्म करता है।

सई फरांजपे- प्रमुख महिला स्क्रिप्ट ग़ाइटर

स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक, अभिनेता सई परांजपे के भीतर रुस और भारत का साझा रक्त है। उनका जन्म 19 मार्च 1938 को हुआ था। उनके पिता रूसी थे और मां महाराष्ट्र से तालुक रखती थीं। फिल्म 'चश्मे बहूर' (1981) का लेखन तथा निर्देशन सई परांजपे ने किया था। नए सिने-दर्शक/सिने-प्रेमी भले ही

ગુજરાત મહિલા

उसका अहं बहुत आहत होता है, यदि कोई उसकी न्यूनता को देखते हए उसकी सहायत करना चाहता है। वह नेत्रहीन लोगों के एक स्कूल का प्रिसपल भी है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात कविता (शबाना आजमी) से होती है, दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, मगर यह सरल न था। जब शादी की

माओवादियों के अंत की तैयारी, 25

अधिक मूलभूत सरकारा सुविधाएँ;
अब दूरी बनाने लगे हैं ग्रामीण



ताइ पराजय का नाम रा पराया था। हों, मगर वे सिने-संसार में एक बड़ा नाम है। आपने 'स्पर्श', 'चश्मे बदूर', 'कथा' जैसी फिल्में अवश्य देखी होंगी। कम-से-कम इनके नाम

इडपा रुडपा, फूर्दपान तथा पेटप्रोफिल्म सोसायटी से जुड़ी सई परांजपे ने मराठी, हिन्दी तथा इंग्लिश तीनों भाषाओं में बच्चों एवं वयस्कों के लिए लिखा। उन्होंने 21 फिल्मों का द्वारा जारा हा ता जारीकूप का मा-में संशय होता है, कहीं कविता उस पर दया और सहानुभूति तो नहीं लादेगी। कहीं उसे सरपरस्ती तो नहीं देने लगेगी। सरपरस्ती जिससे

कर जल म जबदस्त गालबारा
कुल 29 माओवादी मारे गए,
नमें उनका सबसे बड़ा नेता 25
ख रुपये का इनामी शंकर राव
आपिल था। दस पाँचौटे में
सहनुभूत अब माओवादियों का साथ
न होकर सुरक्षा बलों के साथ है।
ताजा मामले में, गृह मंत्रालय ने
इन उग्रवादियों की गतिविधियों पर
आरोपीतों से नज़र रखी और
आदालन का शुरूआत हुई, जहाँ
माओवादियों ने भूमिहीन किसानों
के साथ मिलकर बड़े पैमान पर
सशस्त्र आंदोलन किया, जिसका
दंड की सरकार १५ की एक से

ज्ञानमुद्देश्य था। इस तुठनड़ में ओवादी आधुनिक हथियारों में, असॉल्ट राइफलों तथा ग्रेनेड चर्चों से लैस थे। फिर भी सुरक्षा बलों ने बेहद आक्रामक ढंग से गबला करते हुए उनका खात्मा किया। छत्तीसगढ़, झारखण्ड के बलों के बड़े हिस्से में एक तरह माओवादियों का राज था और उनसे उनका आसान नहीं था। न लोगों ने छत्तीसगढ़ के घने व विस्तृत जगल नहीं देखे हैं, हीं यह बताना जरूरी है कि वहाँ माओवादियों की चप्पे-चप्पे पर नजर ठीं है और उनके कैडर हर जगह चेरे रहते हैं। उन्हें हथियारों का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता और धात लगाकर हमला करने वाले उन्हें महारत हासिल हैं। पिछले उ वर्षी से केंद्र सरकार ने माओवादियों पर लगाम कस्ती शुरू की दी है। गृह मंत्रालय ने इनसे घटने के लिए सुरक्षा बलों को कैवल आधुनिकतम हथियार देना चाहा है, बल्कि अन्य माध्यन भी। माओवादियों से घटने में सबसे बड़ी समस्या यह ही है कि राज्य सरकारें पर्याप्त ज्ञान सारा संभव रक्षा जार जब सूचना बिल्कुल पक्की हो गई, तो राज्य के विरिष्ट पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बीनागुंडा और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चलाया। दिन में चलाए गए इस ऑपरेशन का लाभ यह हुआ कि सुरक्षा बलों को सभी कुछ साफ दिख रहा था और वे उन पर हावी हो गये। और बड़ी संख्या में माओवादियों को जान से हाथ थोना पड़ा। सुरक्षा बलों की आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक चार महीने में लगभग 80 माओवादी मारे गए हैं और 125 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं तथा 150 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया है। यह केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच सामंजस्य से संभव हुआ है। गृह मंत्रालय इस मामले में दृढ़ संकलिप्त है कि माओवादियों से सख्ती से निपटना है, लेकिन बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2019 के बाद से 250 से भी ज्यादा सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं। इन माओवादियों के कारण राज्य का पहा दो सरकार भी उनके से जवाब नहीं दे पाई। इसी आंदोलन की तर्ज पर कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिन) ने छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, ओडिशा आदि में हिंसक आंदोलन किया। बंगाल के आंदोलन के विपरीत यहाँ सिद्धांतों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपना वर्चस्स स्थापित करने की जिद है। इन माओवादियों के कैडर पैसे की वसली करते हैं। खनन कार्य में लगी कंपनियों से मोटी रकम वसूली जा रही है। लेकिन अब समय बदलने लगा है और केंद्र सरकार माओवादियों से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर नक्सल प्रभावित जिलों के लिए नई योजनाएं भी बनाई हैं। इसके तहत उन्हें 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने की बड़ी योजना पर काम हो रहा है। इस तरह के कल्याणकरी कार्यों से ग्रामीण माओवादियों से दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि इस तरह के प्रयासों के कार्यान्वयन

